

अटल जी का मार्गदर्शन

मित्रों आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का समापन है। यह बैठक अत्यंत नाजुक मौके पर हो रही है। आज आपातकाल की बत्तीसवीं वर्षगांठ है तो आने वाले दिनों में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होना है। दोनों अलग-अलग मुद्दे हैं मगर इतिहास में दोनों की जड़ें एक-दूसरे से मिली हुई हैं। आपातकाल लगा था सन् 1975 में। मगर इसका बीजारोपण सन् 1967-69 में ही हो गया था। विशेषकर 1969 में देश के पांचवें राष्ट्रपति के चुनाव के समय। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध अपनी पसंद के प्रत्याशी को खड़ा कर हरवा दिया था। वह एक असुरक्षित प्रधानमंत्री का ऐसा हताशा भरा कदम था, जिसकी परिणति कांग्रेस पार्टी के विभाजन और अंततः देश पर आपातकाल के रूप में सामने आई। भविष्य के प्रति आशंकित एवं असुरक्षित नेतृत्व कब जाने, क्या कर जाए – कहा नहीं जा सकता।

उस समय के कांग्रेस नेतृत्व की भयग्रस्त मानसिकता तो समझ में आती है मगर वर्तमान कांग्रेस में वैसी स्थिति तो नहीं है। फिर नेतृत्व के ऐसे लक्षण क्यों ? क्या कहीं कुछ गड़बड़ है। हमारा यह सुनिश्चित मत रहा है कि सभी संवैधानिक पदों की गरिमा और उनकी परस्पर नियंत्रण और संतुलन की भूमिका बनी रहनी चाहिए ताकि कोई भी अधिनायकवादी न बन सके। 1975 में जब यह संतुलन बिगड़ा तो आपातकाल के रूप में सामने आया। यदि उस समय राष्ट्रपति महोदय (स्व. फखरुद्दीन अली अहमद) प्रधानमंत्री को समझाते और आंखें मूंद कर इस घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं करते तो देश के लोकतंत्र पर ग्रहण नहीं लगता।

राष्ट्रपति पद देश का सर्वोच्च पद है। इसे राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। ऐसे पद पर आम सहमति से निर्णय हों तो ज्यादा अच्छा है। जब हमारी सरकार के समय ऐसा मौका आया तो हमने आम सहमति के आधार पर डा. कलाम को राष्ट्रपति चुना। मगर इस बार देश के भावी राष्ट्रपति के नाम पर आम सहमति बनाने के प्रयास ही नहीं हुए। सत्ता पक्ष ने जब अपना प्रत्याशी तय कर लिया तो हमसे समर्थन मांगने के लिए फोन किया। सहमति निर्णय लेने के बाद नहीं, निर्णय लेने के पहले बनती है।

केन्द्र में सत्तारूढ़ पक्ष को जवाब देना होगा कि उसने इस पद के लिए आम सहमति बनाने के प्रयास क्यों नहीं किए ? वर्तमान राष्ट्रपति डा. कलाम के जिस वक्तव्य पर केन्द्र के मंत्रियों ने निंदा की, वह निंदनीय है। सरकारी नेतृत्व को ऐसे मंत्रियों के असभ्य आचरण के लिए सार्वजनिक निंदा करनी चाहिए। सत्तारूढ़ मोर्चे के एक घटक (सीपीआई) के महासचिव का यह कहना भी आश्चर्यजनक है कि उन्होंने श्री शिवराज पाटिल की उम्मीदवारी का विरोध इसलिए किया कि लोकसभाध्यक्ष रहते समय उन्होंने भाजपा के प्रति नरम रुख अपनाया। सत्तारूढ़ मोर्चा क्या ऐसा लोकसभाध्यक्ष चाहता है जो सिर्फ सत्तारूढ़ दल का वफादार बन कर रहे! मैं नहीं समझता कि कोई भी स्पीकर सदन में विपक्षी दलों के सहयोग के बगैर सदन की कार्यवाही का संचालन सही रूप से कर सकता है। परन्तु यह सोच संवैधानिक पदों को सत्तारूढ़ दल के लिए प्रतिबद्ध (Committed) बनाने की ओर संकेत करती है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।

राष्ट्रपति पद के कांग्रेसी प्रत्याशी का हमारा विरोध, इसी मानसिकता का विरोध है। एनडीए ने इसलिए श्री भैरोंसिंह शेखावत जैसे वरिष्ठ राजनेता, पचपन वर्षों से लगातार राजनीति में सक्रिय, सूझ-बूझ वाले नेता का समर्थन करने का निर्णय किया है। आज देश को उनके जैसे परिपक्व तथा निष्पक्ष नेतृत्व की जरूरत है।

अध्यक्ष जी ने भारत अमेरिका परमाणु समझौते के दुष्परिणामों का उल्लेख अपने भाषण में किया था। राजनैतिक प्रस्ताव में भी इसकी चर्चा है। हमने इसके दुष्परिणामों को देखते हुए लगातार इसका विरोध किया है। भारत सरकार ने अभी हाल में टास्क फोर्स का गठन किया है जो निरस्त्रीकरण तथा परमाणु अप्रसार जैसे मुद्दों पर भारत का जो दृष्टिकोण रहा है उनमें परिवर्तन लाने के मुद्दे पर विचार करेगा। मुझे इस समय इस टास्कफोर्स के गठन की बात समझ में नहीं आई। क्या हम इस टास्कफोर्स के माध्यम से उन मुद्दों पर हम अपनी नीति में बदलाव करना चाहते हैं, जैसा अमेरिका चाहता है ? सरकार को इस बारे में अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए।

मित्रों, मुद्दे और भी हैं। हमें उन मुद्दों को उठाकर जनसंघर्ष करना चाहिए। जहां हमारी सरकारें हैं वहां हमें जनता की सेवा करने तथा अच्छी सरकारें चलाने का कीर्तिमान स्थापित करना चाहिए। संघर्ष और सुशासन हमारी पहचान बननी चाहिए। महंगवाई, किसानों की आत्महत्याएं, लोगों की छोटी-छोटी जरूरतों को लेकर जुट जाने की जरूरत है।

हमारी सक्रियता चुनाव सम्बन्धी होने के साथ-साथ सामान्य समय में भी रहे। हम सिर्फ चुनावी मशीन नहीं हैं। हम बारह मास चलने वाले दल के स्वरूप को बनाए रखें।

धन्यवाद!